



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

त्र. 288]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 1990/कार्तिक 25, 1912

No. 288]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 1990/KARTIKA 25, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1990

(मंज्ञा ओ-17011/5/82-भी.एफ.एस.) भारत सरकार
ने 17 जून, 1985 की अपनी अधिगूचना संख्या ओ-
17011/3/78-जी.ओ.पी. द्वारा केन्द्रीय सरकार प्रत्याभूति
योजना की मानवी पंचवर्षीय योजना में 1-4-1985 से
31-3-1990 तक की अवधि के लिए पंचम घरण के रूप
में जारी रखना अधिपूर्वित किया था, ताकि उसमें विनिर्दिष्ट
उपभोक्ता सहकारी समितियों और अन्य सहकारी संस्थाएं
घटे मार्जिन पर बैंकिंग भ्रमिकरणों से कार्यकर पूर्जी के लिए
ऋण प्राप्त कर सकें।

2. उपभोक्ता सहकारी समितियों को बैंकिंग संस्थानों
में 10 प्रतिशत के घटे हुए मार्जिन पर कार्यकर पूर्जी की मांग

की बढ़ती हुई आवश्यकताओं पर विचार करते हुए, भारत
सरकार ने केन्द्रीय सरकार प्रत्याभूति योजना को आठवीं
पंचवर्षीय योजना प्रर्थात् 1-4-1990 से 31-3-1995 तक
5 वर्ष की और अवधि के लिए अलाने का निर्णय किया
है।

3. मब महकारी संस्थाएं जो कार्य साधक के लिए
विनीय संस्थाओं में इस योजना के अन्तर्गत ऋण लेना
चाहेंगे उनको एक प्रतिशत की प्रतिवर्ष की दर से गारंटी
फीस देय होगी।

4. उपर्युक्त विनियोग के अनुसरण में, भारत सरकार,
उपबंध-1 में दिए गए प्रत्याभूति विलेख प्रृष्ठ में, किसी भी
शीर्ष/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, बैंककारी कम्पनी (उपक्रम
का अर्जन तथा अन्वरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित
और कार्य कर रहे किसी भी बैंक/भारतीय स्टेट बैंक अधि-
नियम, 1955 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय
स्टेट बैंक (ममनुवंगी बैंक अधिनियम, 1959) में यथा

परिवाधित किसी समनुदंगी बैंक के साथ उनके द्वारा निम्नलिखित को दिए गए प्रतिभूति अग्रिम धनों की बाबत, करार करने पर विचार करेगी, अर्थात् :—

- (1) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ
- (2) उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियों के सभी राज्य परिसंघ ।
- (3) सभी थोक/केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी सोसायटियों ।
- (4) किसी भी नाम से रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता वस्तुओं के कारबार में लगे हुए सभी राज्य स्तरीय सहकारी परिसंघ, परन्तु इस प्रत्याभूति के अधीन संरक्षण केवल उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिए उनकी कामकाज पुंजी संबंधी अपेक्षाओं तक ही निर्बंधित रहेगा ।
- (5) किसी भी नाम से रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के खुदरा कारबार में लगी हुई ऐसी सभी सहकारी संस्थाएं, जिनका विक्रय आवर्त कम से कम 20 लाख रुपये प्रति वर्ष है तथा सहकारिता की दृष्टि से अत्यविकसित राज्यों/असम, बिहार, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैण्ड) में ऐसी वे संस्थाएं जिनका न्यूनतम वार्षिक विक्रय आवर्त 10 लाख रुपये है ।

5. केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति, ऊपर पैरा 4(1) से 4(5) में उल्लिखित सभी सहकारी संस्थाओं को ऐसे माल को गिरवी या आडमान के बदले में, जिसके अन्तर्गत वही क्रूर, प्रत्याभूतियां, विनिधान तथा अन्य जंगम सम्पत्ति भी हैं, प्रतिभूति लिखित पूर्व अनुमोदन से, 1-4-1995 से पूर्व वाली विनिर्दिष्ट अवधियों के लिए दिए गए प्रतिभूति उधारों तथा अग्रिम धनों की बाबत ही उपलब्ध होगी। बैंकों को ऐसे उधारों तथा अग्रिम धनों पर केवल 10 प्रतिशत का मार्जिन रखना है। किसी सोसायटी को दिए गए किसी ऐसे उधार या अग्रिम धन की बाबत केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति के अधीन देयता, निम्नलिखित में से जो भी कम है वहां तक सीमित होगी, अर्थात् :—

- (1) उस तारीख को, जिसको करार के निवधनों के अनुसार मांग की सूचना बैंक द्वारा जारी की गई है सहकारी सोसायटी के नाम बैंक की वहियों में वस्तुतः बकाया सब प्रत्याभूत उधारों तथा अग्रिम धनों की रकम का 25 प्रतिशत; या
- (2) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ की दशा में 150 लाख रुपये (एक करोड़ पचास लाख रुपये), सभी राज्य स्तरीय परिसंघों को, जिनके अन्तर्गत पैरा 4(4) में उल्लिखित सहकारी संस्थाएं भी हैं दशा में 100 लाख रुपये (एक करोड़ रुपये) तथा अन्य सभी सहकारी संस्थाओं की, जिनके अन्तर्गत पैरा 4(4) में उल्लिखित संस्थाएं भी हैं,

जो हे उनके कारबार का रेवन महानगरों में है या कहीं और है, दशा में 60 लाख रुपये (साठ लाख रुपये) इनमें से जो भी कम हो ।

6. इस अधिसूचना के अनुसरण में प्रत्याभूति, सरकार के लिखित पूर्व अनुमोदन से, 1-4-1995 से पूर्व वाली विनिर्दिष्ट अवधियों के लिए दिए गए प्रतिभूति उधारों तथा अग्रिम धनों की बाबत उपलब्ध होगा। 1-4-1995 को या उसके पश्चात प्रथम बार दिया गया कोई भी उधार या अग्रिम धन और 31 मार्च 1995 को विद्यमान किसी उधार या अग्रिम धन की बाबत बकाया रकम में कोई भी वृद्धि प्रत्याभूति के अन्तर्गत नहीं आएगी। इस प्रत्याभूति के कारण उत्पन्न हुए केन्द्रीय सरकार का दायित्व 31 मार्च, 1995 को कारबार के बंद होने के समय समाप्त हो जाएगा।

7. सोसायटी, भारत के राष्ट्रपति के साथ इससे उपावद्ध प्रत्याभूति-विलेख को प्रथम अनुसूची में उपबंधित प्रलैप में एक करार करके निम्नलिखित के लिए वचनबद्ध होगी, अर्थात् —

- (क) उधार, अग्रिम धन या नकद उधार मंजूर करते समय बैंक द्वारा अधिकथित शर्तों के अनुसार बैंक के देयों को नियमित रूप से और जीघ्रता से संदर्भ करने के लिए;
- (ख) लाभ कमाने की दृष्टि से सोसायटी का कारबार तपतरापूर्वक करने के लिए;
- (ग) केन्द्रीय सरकार को उन सब धनराशियों का प्रतिसंदाय मांग पर बिना किसी आपत्ति के करने की प्रत्याभूति देने के लिए, जो बैंक द्वारा सोसायटी की ओर से बैंक को सदाय करने में चूक के कारण केन्द्रीय सरकार से बयूल की जाए;
- (घ) स्टाकों के नियमित सत्यापन की पठति को कार्यान्वयित करने, तदोपरान्त, स्टाक में हुई कमियों का तत्काल निर्धारण करने, उसके लिए जिम्मेदारी नियत करने और जिम्मेदार व्यक्तियों से उनके मूल्य की वसूली करने के लिए;
- (इ) सोसाइटियों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों को उधार देने की सुविधाएं देने में कड़ी सावधानी बरतने और साथ ही उसकी व्यवस्थित तथा तत्काल वसूली के लिए उपाय करने के लिए;
- (च) प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख को तिमाही व्यापार और लाभ तथा हानि और तुलनपत्र का और साथ ही सोसाइटी के कार्यकरण की तिमाही प्रबंध रिपोर्ट का तैयार किया जाना सुनिश्चित करने और प्रत्येक तिमाही में उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजने के लिए;
- (छ) सोसाइटी की सम्पत्तियों और आस्तियों, को उन बिल्लगमों तथा कुकियों से भिन्न बिल्लगमों और कुकियों से मुक्त रखने के लिए, जो बैंक के पक्ष में हो तथा जिनके बारे में सरकार ने बैंक को

प्रत्याभूति दी है अथवा जो राज्य सरकारों के पक्ष में है; और

(ज) केन्द्रीय सरकार या इस नियमित उसके द्वारा नाम विनियोगित किए गए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सोसायटी के लेखांशों तथा उसके कार्यकरण की परीक्षा करने के लिए, सभी सुविधाओं प्रदान करने के लिए।

यह नामर धन राशि निकालन की तारीख से पूर्व निष्पादित किया जाएगा। बैंक कोई संदाय नब तक नहीं करेगा जब तक कि हस्ताक्षरित करार तथा प्रत्याभूति विनेश्व के द्वितीय अनुसूची में उपब्रधित प्रक्षय में सम्पन्न पत्र नहीं दें दिए जाते हैं।

8. केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति, बैंक द्वारा दिए गए उधारों तथा अग्रिम धनों पर ब्याज के लिए लाग नहीं होती है।

9. प्रत्येक बैंक ऐसे सभी वक्तव्य-पक्षों या वसूल न की गई प्रतिभूतियों को, जो बैंकों को उनके द्वारा सोसायटी को दिए गए ऐसे उधारों के बारे में उपलब्ध हों, केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति के अधीन बैंक द्वारा दिए गए उधारों तथा अग्रिम धनों की वावन बैंकों को देय सम्पूर्ण वकाया की उनके द्वारा वसूली के बाद की तब तक प्रतिधारित रखेगा जब कि प्रत्याभूति दाता के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिपूर्ण रकम की वसूली न हो जाए।

10. बैंक प्रत्याभूति विनेश्व की किसी द्वितीय अनुसूची में दिया गया इस आशय का एक सम्पत्ति पत्र सोसायटी में अभिप्राप्त करेगा और केन्द्रीय सरकार को देगा कि सोसायटी निम्नलिखित रूप में करार करती है कि—

(क) वह प्रत्याभूति के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा बैंक की संदत्त की गई किसी रकम पर ब्याज उसी दर में जिस दर से सोसायटी का दिए गए उधार या अग्रिम धन पर ब्याज बैंक द्वारा प्रभारित किया गया है या किया जाए, तब तक देती रहेगी जब तक उक्त रकम केन्द्रीय सरकार को संदत्त या उसके पक्ष में समर्योजित नहीं कर दी जानी;

(ख) वह उस तारीख के पश्चात जिसको प्रत्याभूति के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने किसी रकम की प्रतिपूर्ति बैंक को की है, किन्तु प्रत्याभूति के अन्तर्गत अनेक बैंक के दावे की पूरी-पूरी मुष्टि हो जाने के पश्चात् और उस समय तक जब तक कि उन रकमों की जो उधार सुदृढ़ सोसायटी द्वारा गंवाया जाये गये थे तो उन रकमों की गई हो जाए तथा प्रभारी भाई द्वारा सोसायटी द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं कर दी जाती, उधार या अग्रिम

धन लेखे सोसायटी द्वारा की गई या उसमें वसूल केवल की गई सब रकमों को प्रतिभूति (केन्द्रीय सरकार) के खाते में जमा होने देगी या जमा करने के निए बैंक को अनुज्ञा देगी।

(ग) सब ऐसे उधारों नवा अग्रिम धनों की वावन बैंक के पक्ष में की प्रतिभूतियों पर सभी अधिकार बैंक के पास होंगे और वह उनका प्रयोग तब तक करता रहेगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार के ऐसे यब दावों की पूष्ट नहीं हो जाती; और

(घ) बैंक ऐसी प्रतिभूतियों के अधीन अपने अधिकारों और दावों का अन्तरण केन्द्रीय सरकार को उस दशा में करेगा जब पश्चात्कार्यत द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए।

11. बैंक का यह समाधान हो जाने की दशा में कि सोसायटी प्रत्याभूति के अधीन दिए गए अग्रिम धन के प्रति बैंक की नियमित विप्रेणण करने में असफल रही है या किसी प्रत्याभूति को चालू रखने के लिए उसकी समाप्ति के पूर्व लिखित रूप में प्रतिभूति का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने में असफल रहती है तो बैंक घटाए गए माजिन पर सोसायटी द्वारा और धन प्राप्त करने की अनुज्ञा नहीं देगा तथा सोसायटी द्वारा सभी आगे के विप्रेणों को प्रत्याभूत छूट के खाते में तब तक जमा करता रहेगा जब तक कि वे पूर्ण रूप से प्रतिसंदत्त नहीं हो जाता।

12. बैंक द्वारा किसी विशिष्ट सोसायटी की वावन केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति का आश्रय एक से अधिक बार नहीं लिया जाएगा। प्रत्याभूति का आश्रय 1 अप्रैल, 1995 से पूर्व किसी भी समय लिया जा सकेगा। बैंक पहले सोसायटी के नाम इस प्रभाव की मांग सूचना जारी करेगा कि वह उस रकम को, जो बैंक द्वारा दिए गए हैं और प्रतिभूति द्वारा प्रत्याभूत किए गए उधारों और अग्रिम धनों के लेखे बैंक को देय हों, उस तारीख से 30 दिन के भीतर संक्षत करे जिसको ऐसे प्रतिसंबंध मांगने का सूचना बैंक द्वारा नामील की गई है। ऐसी मांग की सूचना की एक प्रतिलिपि प्रतिभूति को भी साथ साथ पृष्ठांकित की जानी चाहिए। यदि सोसायटी उक्त 30 दिन की अवधि की समाप्ति तक रकमों का संदाय नहीं करती है तो बैंक केन्द्रीय सरकार के नाम मांग की सूचना जारी करेगा। केन्द्रीय सरकार बैंक को प्रत्याभूति के अधीन संदाय रकम की प्रतिपूर्ति उस तारीख के 90 दिन के भीतर करेगी जिसकी उसे प्रत्याभूति की आश्रय लेने और संदाय का दावा करने की बैंक की सूचना प्राप्त हों।

13. इस अधिसूचना के अनुसरण में प्रत्याभूति चाहते वाला बैंक, किसी उधार या अग्रिम धन की वावन सरकार की प्रत्याभूति का आश्रय लिए जाने की दशा में केन्द्रीय सरकार के नाम इन रकमों को जमा करने के लिए वचनबद्ध होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत उधारों तथा अग्रिम धनों की पूरी वसूली बैंक द्वारा सोसायटी से लिए जाने के पश्चात सोसायटी से वसूल की जाए। बैंक के लिए यह

बाध्यकर होना कि वह प्रत्याभूति के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा रकम की प्रतिपूर्ति कर दिए जाने के पश्चात उपरोक्त रीति से कार्यवाही करे।

14. उपरोक्त खण्डों में निर्दिष्ट बैंक की बाध्यनाम, उस समय तक जारी रहेगी जब तक कि वह रकम जिसको प्रत्याभूति के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति कर दी गई है केन्द्रीय सरकार को संदर्भ नहीं कर दी जाती है या केन्द्रीय सरकार के नाम जमा नहीं कर दी जाती है या जब तक केन्द्रीय सरकार उक्त रकम का समायोजन घपने द्वारा बैंक या सोसायटी को मंदेय किसी अन्य रकम से करते या उस रकम को वसूली का अधित्यजन करने के लिए सहमत नहीं हो जाती।

15. संबद्ध राज्य की सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार बैंध और प्रशासनिक रूप में सोसायटी के कार्यकरण का नियमित पर्यवेक्षण करने तथा सोसायटी के कार्यों और गतिविधियों में किन्हीं प्रतिकूल लक्षणों के पाए जाने की दशा में या यदि सोसायटी द्वारा अनियमित विप्रेषणों या सोसायटी के कार्यकरण में किन्हीं अन्य अवांछनीय विस्तीर्ण बातों के संबंध में बैंक द्वारा कोई रिपोर्ट की जाने की दशा में समुचित उपचारात्मक उपाय करने के लिए भी सक्षम प्राधिकारी होगा। यह स्पष्टतः समझ लिया जाए कि यह प्रत्याभूति के बल तभी दी जाएगी जब संबद्ध राज्य की सहकारी सोसायटियों के रजिस्ट्रार द्वारा संबंधित प्रस्ताव की सिफारिश की जाएगी। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा की गई सिफारिश को ऐसे रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया यह आश्वासन समझा जाएगा, कि सोसायटी के कार्यों और गतिविधियों के संबंध में बैंक और/या भारत सरकार से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, समुचित उपचारात्मक उपाय किए जाएंगे।

16. भारत सरकार के ऐसे मन्त्रालय में, जो उपभोक्ता सहकारी समितियां, नई दिल्ली से मंबवहार करता है, निदेशक उपसचिव की पक्षित या उससे उच्चतर पंक्ति का कोई अधिकारी हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्मिलित रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिसूचना के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति के संबंध में बैंकों के साथ प्रत्याभूति का विहित करार करने के लिए प्राधिकारी होगा। अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सभी बैंकों को सलाह दी जाती है कि यदि वे केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो वे ऊपर उपदण्डित मन्त्रालय में प्रत्याभूति तथा प्रवर्तन के भारसाधक अधिकारी से संपर्क स्थापित करें।

डा. प्रदीप मोंगा, निदेशक

प्रत्याभूति विलेख

एक पक्षकार के रूप में भारत के गढ़पति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात प्रतिभू कहा गया है) और हमरे पक्षकार के रूप में जो बैंककारी कम्पनी (उपरोक्त का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1970

के अधीन गठित तथा संचालित बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक जो भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन गठित किया गया निगम है।

(बैंक का नाम) जो भारतीय स्टेट बैंक (समनुपगी बैंक) अधिनियम, 1959 के अधीन गठित किया गया निगम है। के अधीन रजिस्ट्रीकून महकारी सोसायटी है, और जिसका कार्यालय में है (जिसे इसमें इसके पश्चात "बैंक" कहा गया है) के बीच 19 के/की दिन किया गया यह प्रत्याभूति-विलेख निम्नलिखित का साधी है :

बैंक द्वारा को (जिसे इसमें इसके पश्चात "सोसायटी" कहा गया है) पश्चात कथित के निवेदन पर, उन मार्जिनों को शिथिल करके जो इस प्रत्याभूति की अनुपस्थिति में बैंक सामान्य रूप से अनुसरण करता, प्रतिभू बैंक को इसमें इसके पश्चात उपबंधित परिमाण तक उधारों और अग्रिम धनों को सोसायटी द्वारा बैंक को प्रतिसंदाय, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर प्रत्याभूति करता है, जो इसमें इसके पश्चात उल्लिखित है :

1. प्रतिभू की प्रत्याभूति, बैंक द्वारा प्रतिभू के लिखित पूर्व अनुमोदन से सोसायटी को विनिर्दिष्ट अवधियों के लिए 1 अप्रैल, 1995 से पूर्व दिए गए किसी ऐसे प्रतिभूत उधार या अग्रिम धन की बाबत ही उपलभ्य होगी जो माल की गिरवी या आडमान के बदले में, जिसके अन्तर्गत वही छूट, प्रतिभूतियां, विनिधान तथा अन्य जंगम सम्पत्ति भी है, दिया गया हो। बैंक ऐसे उधारों और अग्रिम धनों के लिए केवल 10 प्रतिशत का मार्जिन रखने के लिए सहमत है।

2. उक्त सोसायटी जो उपरोक्त रूप में विए गए उधार या अग्रिम धन की बाबत प्रतिभू का वायित्व, किसी भी समय, निम्नलिखित में से जो भी रकम सबसे कम हो उससे प्राधिक नहीं होगा :—

(1) उस तारीख को जिसको प्रतिभू के नाम मांग की सूचना इसके खंड (3) के उपबंधों के अनुसार बैंक द्वारा जारी की जाती है, सोसायटी के नाम बैंक द्वारा जारी की जाती है, सोसायटी के नाम बैंक की बहियों में वस्तुतः बकाया प्रत्याभूत किए गए उधारों तथा अग्रिम धनों की रकम का पच्चीस प्रतिशत; या

(2) लाख रुपये।

3. बैंक 1 अप्रैल, 1995 से पूर्व किसी भी समय प्रतिभू को प्रत्याभूति का आसरा इसमें इसके पश्चात विनिर्दिष्ट नीति से ले लेंगे, अर्थात् :—

(1) बैंक ने मोराइटी के नाम इस मांग की गुच्छा जारी करेगा कि वह उन रकमों को, जो उसे बैंक द्वारा दिए गए और प्रतिभू प्रत्याभूत किए गए

उधारों और अग्रिम धनों लेखे अपने को देय हों, उम तारीख से तीस दिन के भीतर संदत करे जिसको ऐसा प्रतिसंदाय मांगने की सूचना बैंक द्वारा उधारी की गई है। उम मांग नोटिस की एक प्रतिलिपि प्रतिभू को भी साथ-साथ पुष्टांकित की जानी चाहिए।

(2) यदि सोसाइटी, यथापूर्वोक्त 30 दिन की अवधि की समाप्ति पर, बैंक द्वारा उम दिए गए और प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूत किए गए उधारों तथा अग्रिम धनों का संदाय नहीं करती है, तो बैंक प्रतिभू के नाम मांग की सूचना जारी करेगा।

(3) बैंक प्रतिभू की प्रत्याभूति का आमरा लेने समय, प्रतिभू को निम्नलिखित विवरण देगा :—

(1) उन मालों का व्यौरा, जिन पर ऐसा उधार या अग्रिम धन दिया गया है जिसकी बाबत प्रत्याभूति का आसरा लिया गया है;

(2) उक्त मालों की बाजार मूल्य; और

(3) निम्नलिखित तारीखों को सोसाइटी के नाम बकाया रकमें :—

(क) वह तारीख जिसको प्रतिसंदाय मांगने की सूचना बैंक द्वारा सोसाइटी के नाम जारी की गई थी— तथा

(ख) प्रतिसंदाय मांगने की सूचना की तारीख से तीस दिन को समाप्ति की तारीख, और

(4) प्रतिभू बैंक को देय रकम की इस प्रत्याभूति में उपबंधित परिमाण तक प्रतिपूर्ति उस तारीख से 90 दिन के भीतर करेगा जिसको प्रत्याभूति का आसरा लेने और संदाय का दावा करने की बैंक की सूचना प्रतिभू ने प्राप्त की हो।

4. इसमें अंतिम प्रत्याभूति इस बात के होते हुए भी प्रतिभू के बिल्डु प्रश्न की जा सकेगी कि कोई प्रतिभृतियाँ जो बैंक ने सोसाइटी से अर्भप्राप्त की हो, बकाया हों, या बमूल न की गई हों।

5. प्रत्याभूति विलेख की प्रथम अनुसूची में उपाबद्ध प्रणय में सोसाइटी भारत के राष्ट्रपति के साथ एक करार करेगी और इसके लिए वचनबद्ध करती है कि वह :—

(क) बैंक द्वारा उधार, अग्रिम धन या नकद उधार मंजूर करते समय अधिकारित शर्तों के अनुसार बैंक के देयों को निर्यातित रूप में और शीघ्रता में संदत करेगी,

(ख) लाभ फसाने की दृष्टि से सोसाइटी का कारधार तत्परतापूर्वक करेगी,

(ग) केन्द्रीय सरकार को उन सब धनराशियों का प्रतिसंदाय, मांग पर बिना पूर्वापीति के करने को भी प्रत्याभूति देसी जो बैंक द्वारा सोसाइटी की ओर से बैंक को संदाय करने में व्यक्तिक्रम के कलस्वरूप केन्द्रीय सरकार से बमूल की जाए,

(घ) स्टार्कों के नियमित सत्यापन की पढ़ति को कार्यान्वित करेगी, तदोपरांत कमियों का तःकाल निर्धारण करेगी, उसके लिए जिम्मेदारी नियम करेगी और जिम्मेदार व्यक्तियों में उनके मूल्य को बमूली करेगी,

(इ) सोसाइटी, सह्यात्मकों और व्यक्तियों को उधार देने की सूचियों का विस्तार करने में बड़ी सावधानी बर्खेगी और साथ साथ उनकी ध्यानित तथा तत्काल बमूली के लिए उपाय करेगी;

(च) प्रत्येक तिमाही को अग्रिम तारीख को तिमाही व्यापार और लाभ तथा हानि और तुलनपत्र का तैयार किया जाना और साथ ही सोसाइटी के कार्यकरण की तिमाही प्रवंध रिपोर्ट का तैयार किया जाना सुनिश्चित करेगी और प्रत्येक तिमाही में उसकी एक प्रति प्रतिभू की घेजेगी,

(छ) सोसाइटी की सम्पत्तियों और आविष्यों को उन विलंगमों तथा कुकियों से मुक्त रखेगी—जो उनके प्रलापा हैं, जो बैंक के पक्ष में हैं तथा जिसके बारे में सरकार ने बैंक को प्रत्याभूति दी है अथवा जो राज्य सरकारों के पक्ष में हैं; और

(ज) प्रतिभू या इस निर्मिति उनके द्वारा नाम निर्देशित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों वो अपने लेखाओं तथा अपने कार्यकरण को परीक्षा करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेगी।

बैंक सोसाइटी को तब तक कोई संदाय नहीं करेगा जब तक कि प्रत्याभूति विलेख को प्रथम अनुसूची के प्रणय में करार तथा द्वितीय अनुसूची में वे सम्पत्ति पत्र पक्षकारों द्वारा सम्यक रूप से निर्धारित करके उसे नहीं दें दिए जाते।

6. बैंक उस प्रत्याभूति के प्रति कलस्वरूप जो उसकी प्रतिभू से उपलब्ध है, निम्नलिखित बातों के लिए सहमत होगा :—

(क) प्रतिभू को ऐसी कोई रकम संबत्त करना या उसके बाते में जमा करना जो प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूत रकम की प्रतिपूर्ति कर दिए जाने को तारीख के पश्चात, प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूत उधारों तथा अग्रिम धनों को पूरी बमूली उसके द्वारा कर लिए जाने के पश्चात सोसाइटी से बमूल की जाएगी,

(ख) ऐसे सब वचन पत्रों या बमूल न की गई प्रतिभृतियों की, जो बैंक द्वारा सोसाइटी ने दिए गए उधारों के बारे में उसे उपलब्ध हों, बैंक को देय

मध्यूर्ण ब्रक्या को उसके द्वारा बसूली के पश्चात्तन भी नव तक प्रतिवारित रखना जब तक प्रतिम् द्वारा प्रतिपूरित रकम की बसूली न दो जाएँ।

(ग) इसकी द्वितीय अनुसूची में उपर्युक्त प्रथम में एक समानि पत्र सोसाइटी से अभिप्राप्त करना और प्रतिम् को देना;

(घ) यदि प्रतिम् द्वारा अपेक्षा की जाएँ जो अपने को देय ब्राह्मण को पूरी बसूली बैंक द्वारा कर दिए जाने के पश्चात् सब ऐसे बचत पत्रों या प्रतिभूतियों को प्रतिम् तथा/या उसके नाम-निर्देशिनी को अंतर्गत करना किन्तु यह नव जब कि प्रतिम् को उसके द्वारा दी गई रकम की प्रतिपूर्ति न की गई हों; और

(इ) इसके उत्तरांचल प्रत्यासुनिविलेख की प्रथम अनुसूची में उपर्युक्त प्रथम में एक करार सोसाइटी से अभिप्राप्त करना और प्रतिम् को देना, जैसा कि उसके घंड 5 में उपर्युक्त किया गया है।

7. प्रतिम् को प्रत्याभूति सोसाइटी को मंजूर किए गए उधारों तथा अभिम धनों और ज्यात्र के बारे में लागू नहीं होंगी।

8. घंड (6) के उपर्युक्तों के अनुसरण में बैंक की बाध्यताएँ उस समय तक जारी रहेंगी जब तक वह रकम जिसकी प्रतिम् द्वारा प्रतिपूर्ति की गई है प्रतिम् को चुका नहीं दी जाती या उसके नाम जमा नहीं करकी जाती या जब तक प्रतिम् अपने द्वारा बैंक या सोसाइटी को संदेत की जाने वाली अन्य शोध्य रकम के साथ उक्त रकम का समायोजन न करने या उस रकम की बसूली का अधित्यजन करने के लिए सहमत नहीं हो जाता।

9. इस सोसाइटी की बाजत प्राप्तिम् को प्रत्याभूति का आसरा बैंक द्वारा एक से अधिक बार नहीं लिया जाएगा और यदि प्रतिम् को प्रत्याभूति का आसरा निया गया है या उसका आसरा लेने के पश्चात् कोई उधार या अभिमधन उस सोसाइटी को दिया जाता है जिसकी ओर से कोई रकम बैंक को प्रतिम् द्वारा की गई है, तो कोई भी ऐसा उधार या अभिमधन बैंक को अपनी जोखिम पर होगा। और ऐसे अर्तिरक्त उधार या अभिमधन के लिए प्रतिम् का कोई दायित्व नहीं होगा।

10. 1 अप्रैल, 1995 को या उसके पश्चात् प्रथम बार दिया गया कोई भी उधार या अभिमधन और 31 मार्च, 1995 को विद्यमान किसी भी उधार या अभिमधन को बाजत बायाय। याम गं कोई भी बदल प्राप्ति डाग प्रथमधन नहीं हो जाएगी। याम गं के दायित्व 31 मार्च, 1995 को कारबार दंड होने के समय भासात हो जाएगा।

11. प्रतिम्, ऐसे उधारों तथा अभिमधनों की बाबत जिनके संबंध में यह प्रत्याभूति बैंक को उपलब्ध है, ऐसी जानकारी और विवरणियाँ बैंक से अभिप्राप्त करने के लिए हकदार होगा। और बैंक ऐसी जानकारी और विवरणियाँ ऐसे अंतरालों पर या ऐसी रीति में देगा जैसी प्रतिम् द्वारा विनियोजित या अपेक्षित की जाएँ।

12. यदि इस प्रकार से उद्भूत या उसके संबंध में या इसके अर्थ या निर्वचन के बारे में अथवा इस कागज की बाबत अन्यथा किसी भी प्रकार या कोई मन्त्रेद या विवाद इसके पक्षकारों के बीच हो तो वह नत्यमय भारत सरकार के ऊपर विधि समाहार (माध्यस्थम) का एवं धारण करने वाले व्यक्तिके एकमात्र माध्यस्थम के लिए निर्विचित किया जाएगा और उसने अधिकारी का विनियोजन अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों पर आवाहकर होगा। यह कोई अपत्ति नहीं होगी कि मध्यस्थ सरकारी सेवक है, उसे उन मामलों में जिनसे यह प्रत्याभूति संबंधित है, कारबाही करनी पड़ी थी या सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के श्रनुकम में वह उन मध्य बातों पर या उनमें से किसी पर, जिनके बारे में विवाद या मन्त्रेद है अपने विवार प्रकट कर चुका है। मध्यस्थम अधिनियम, 1940 के उपर्युक्त या उसके कोई कानूनी उपाय्तरण या पुनः अधिनियमित ऐसे माध्यस्थम को लागू होंगे। माध्यस्थम कार्यविधियाँ उस स्थान पर को जाएगी जिसे माध्यस्थ विनियोजित करे। मध्यस्थ की यह हक होगा कि वह पंचाट करने का समय पक्षकारों को समानि से समय समय पर बढ़ा सके।

13. इस प्रत्याभूति विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क, यदि कोई हो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा।

14. इसके साक्षस्वाक्षर्य प्रतिम् और बैंक ने यह विनेश्व ऊपर उल्लिखित दिन और वर्ष को सम्मुख रूप से नियमित कराया है।

निदेशक (प्रत्याभूति) तथा प्रत्याभूत भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से परिसर में कार्यकारी भारत सरकार के ऐसे मंत्रालय में जो उपमोक्ता सहकारी समितियों में संबंधवाहक करता है।

निम्ननियिति की उपस्थिति में साक्षी

(1)

(2)

प्रथम अनुसूची

कागज

एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति, (जिन्हें इसमें छोड़कर "कर्तव्य सरकार" कहा गया है), जिस पद के अन्यान्, जब वह अंदरुप में अभिमंति या उपर्युक्ति न हो, उसके पद उत्तराधीन और समनुदर्शिनी भी समझे जाएंगे।

प्रति द्वारा प्रभासाद के रूप में —
अधीन गजस्तीकृत — मत्रकारी
ओमाइटी है थोर जिसका गजस्तीकृत/कंद्रीय/मख्य कार्यान्वय

में है (जिसे इसमें इसके पश्चात “सोसाइटी” कहा गया है जिस पद के अन्तर्गत, नव तक संदर्भ से अपवाजित या उसके विष्टु न हो, उसके नियादन, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनु-
ज्ञात समन्वेशी और उत्तराधिकारी भी समझे जाएंगे) के
बीच आज 19 ————— के/की ————— दिन किया गया यह करार
नियालियित का साक्षी है:-

बैंक के द्वारा, सोसायटी को उधार अप्रिम धन, नकद उधार सीमाएँ और मन्त्र बैंकारी भूविधाएँ और गोकर्ण देने के प्रतिफल स्वरूप, अन्य बातों के साथ लाल बैंक द्वारा सोसाइटी को दिए गए उधार और अप्रिम धन के प्रकार भाग के प्रति संशय को केन्द्रीय सरकार के द्वारा प्रत्याभूति देने पर, सोसाइटी केन्द्रीय सरकार से एतदुरा वचनबद्ध करती है, कि वह :—

- (1) वैकं द्वारा, उधार, अप्रिम धन या नकद उधार मंजूर करते समय अधिकारित शर्तों के अनुसार वैकं के शोध्यों को नियमित रूप से और शीघ्रता से संदर्भ करेगी ;

(2) लाभ कमाने की दृष्टि से सोसाइटी का कारोबार नत्यगतापूर्वक करेगी ;

(3) स्टाकों के नियमित संथापन की पद्धति को कार्य-न्वित करेगी, तदोपरान्त कमियों का तत्काल निश्च-रण करेगी, उसके लिए जिम्मेदारी नियम करेगी और जिम्मेदार व्यक्तियों से उनके मूल्य की बसूली करेगी ।

(4) सोसाइटियों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों को उधार देने की सुविधाओं का विस्तार करने में बड़ी साक्षाती बरतेगी और साथ ही उनकी व्यवस्थित तथा तत्काल बसूली के लिए उपाय करेगी ;

(5) प्रत्येक निमाही की अंतिम तारीख को निमाही छापार और लाभ तथा हानि और तुलन-पत्र तैयार किया जाना और साथ ही सोसाइटी के कार्यकरण की तिमाही प्रबंध रिपोर्ट का तैयार किया जाना सुनिश्चित करेगी और प्रत्येक तिमाही में उसकी एक ब्रह्म केन्द्रीय मरकार को और राज्य मरकार को भी भेजेगी

(6) सोसाइटी को सञ्चालनियों और आदिनियों को विवरणम् तथा कुक्कियों से मुक्त रखेगी – जो उनके ग्राहा है, जो जैक के पत्र में हैं तथा जिनके बारे में मरकार ने बैक को प्रत्याभूति दी है अथवा जो राज्य मरकार के पक्ष में है, और

(7) केन्द्रीय राज्यालय या हांग विभाग उपरि ग्रामीण विकास नियंत्रित किए शामि किसी व्यक्ति या व्यक्तिगतों को अपने लेखा तथा अपने कार्यकरण की परीक्षा करने के लिए सभी गवाहाओं प्रश्नन करेगी।

2. सोमाइटी केंद्रीय सरकार की उन सब धनराशियों को प्रतिक्षेप्ता मांग पर निरा पूर्व आपत्ति के, कर्गत की प्रस्थामूर्ति करती है औ वैक द्वारा केंद्रीय सरकार पर सोमाइटी की ओर से लिए गए व्यक्तिक्रम के फलस्वरूप बहुल की जाए।

3. उपरोक्त खण्ड 2 के मिवाय, इस करार में उद्भूत होने वाले या इसमें किसी प्रकार से संबद्ध या संवेशित सभी विवाद और मतभेद भारत सरकार के ऊपर विधि सनातनकार (माध्यस्थम) का पद धारण करने वाले व्यक्ति के एक मात्र माध्यस्थम के लिए निर्देशित किए जाएंगे। यह कोई आपत्ति नहीं होगी कि मध्यस्थ सरकारी सेवक है या कि उसने विवाद या मतभेद के सभी या किसी सामने पर अपने विचार प्रकार किए थे। भारतीय माध्यस्थम अधिनियम के उपर्युक्त ऐसे माध्यस्थमों को लागू होंगे। मध्यस्थ का पंचाट अंतिम होगा और दोनों पक्षकारों पर आवेदकर होगा।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और
उसकी ओर से —————
(नाम और पदाधिकार) डारा हस्ता-
क्षरित सोसाइटी के प्राधिकृत प्रति-
निधि (प्रतिनिधियों) डारा हस्ताक्षरित
(नाम और पदाधिकार)

साधी-

- (1)

ਪੰਜਾਬ ਅਨੱਸੂਚੀ

समाज-पत्र

३८

- बैफ
 - भारत के राष्ट्रपति।

द्वारा (जिसे इसमें
इसके पश्चात “बैक” कहा गया है) —————
को दिए गए उदारों तथा अधिकारियों के एक भाग में प्रति
संदाय को प्रत्याभूत करने के लिए भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें
इसमें इसके पश्चात “गणपति” कहा गया है) के सहमत हो
जाने के फलस्वरूप हम यह करार करते हैं कि कोई भी बचन
पत्र और माल की गिरवी या आड़पान के क्षमा में कोई भी
प्राप्तिमुनि, जिनके अन्तर्गत वही, अण प्रतिभूतियाँ, विनिधान
और यन्म जंगम सम्पत्ति थी तो जो ऐसे उदारों और अधिकारियों
के संबंध में आप बैक को दी है और हमारे द्वारा वी
जाए, हम ब्रात के हीने हुए भी अस्तित्व में रहेंगी तथा बैक

द्वारा प्रतिचालित की जा रही कि राष्ट्रपति द्वारा बैंगी ना दी गई प्रत्याभूति के अनुसरण में, राष्ट्रपति ने हमारे खाते में की किसी कमी को पूरा कर दिया है, हम यह और करार करने हैं कि :—

- (क) हम राष्ट्रपति को प्रत्याभूति के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा बैंक को दी गई किसी रकम पर व्याज, उसी दर से जिस घर से हम को दिए गए उधार या अग्रिम धन पर व्याज बैंक द्वारा प्रभारित किया गया है या किया जाए, तब तक देते रहेंगे जब तक उक्त रकम राष्ट्रपति को मंबत्त या उनके पक्ष में समायोजित नहीं कर दी जाती ;
- (ख) उस तारीख के पश्चात जिसकी अपनी प्रत्याभूति के अनुसरण में राष्ट्रपति ने किसी रकम की बावत बैंक की प्रतिभूति की है किन्तु राष्ट्रपति को प्रत्याभूतियों के अन्तर्गत आने वाले उधारों तथा अग्रिम धनों की बावत बैंक के दावे को पूरी पूरी सुषिट हो जाने के पश्चात और उस समय तक जब तक उन रकमों की, जिनकी राष्ट्रपति द्वारा प्रतिपूर्ति की गई है, उन पर व्याज तथा प्रभारों सहित, हमारे द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं कर दी गई था हमसे अमूल की गई सब रकमों को जमा करने के लिए बैंक की अनुज्ञा देंगे ।
- (ग) ऐसे सब उधारों तथा अग्रिम धनों की बावत बैंकों के पक्ष में की गई प्रतिभूतियों के बारे में सभी अधिकार बैंक के पास रहेंगे और वह उनका प्रयोग तब तक करता रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति के ऐसे सभी दावों की, जो खंड (ख) में निर्दिष्ट किए गए हैं, तुष्टि नहीं हो जाती, और
- (घ) ऐसी प्रतिभूतियों के अधीन अपने अधिकारों तथा दावों या बैंक उस दशा में राष्ट्रपति को अंतरण करेगा, जबकि उनके द्वारा या उनकी ओर में ऐसी अपेक्षा की जाए ।

सोसाइटी के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित (नाम और पदा-भिमान)

साक्षी—
(1)
(2)

अनुबंध-II

अधिभूतना संख्या औ— 17011/2/89— सी. एफ. एम. दिनांक 1-11-1990 के द्वारा परिचालित केन्द्रीय मरकार की प्रत्याभूति योजना के तहत राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंकों में घटी दरों पर कार्यकर पूँजी ऋण प्राप्त करने के लिए

केन्द्रीय नरसार प्रत्याभूति सी. पंजी द्वेषु प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया :

जो संस्था केन्द्रीय मरकार की प्रत्याभूति (गारंटी) चाहती है, उसे अपना प्रत्यावर निम्नलिखित भूचना और कागजात के साथ प्रमुख करना होगा :—

- (1) निर्धारित फार्म (परिशिष्ट-I) में संस्था का व्यौरा दिया जाए तथा साथ ही यदि उसकी विक्री और लाभकारिता में किसी वर्ष विशेष में कमी आई है तो उसके कारण दिए जाएं ।
- (2) निवेशक मंडल का संकल्प (परिशिष्ट-II), जिसमें केन्द्रीय सरकार की गारंटी के तहत किसी वैक विशेष में कार्यकारी ऋण प्राप्त करने के लिए संस्था के निर्णय का उल्लेख हो, जो श्रावेदन पत्र की तारीख से तीन माह से अधिक पुराना न हो, भेजा जाए और साथ ही उसमें आवश्यक घोषित कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए व्यक्ति/व्यक्तियों को भी प्राधिकृत किया गया हो ।
- (3) अधिभूतना की प्रथम अनुमूली में दिया गया करार, प्रपत्र, जिस पर प्राधिकृत व्यक्तियों और पूरे पतों सहित दो साक्षियों के विधिवत हस्ताक्षर हों, भेजा जाए ।
- (4) अधिभूतना की दूसरी अनुमूली में दिया गया सम्मतिपत्र, जिस पर प्राधिकृत व्यक्तियों और पूरे पतों सहित दो साक्षियों के विधिवत हस्ताक्षर हों, भेजा जाए ।
- (5) पिछले चार सहकारी बैंकों के लिए लेखाओं का लेखा परीक्षित कच्चा विवरण अर्थात् व्यापार और लाभ तथा हानि लेखा व तुलनपत्र मेजा जाए । इनमें से कम से कम दो बैंकों के लेखा विवरण लेखा परीक्षित हों तथा साथ साथ बाद के लमाही/तिमाही के कच्चे लेखा हों । लेखा परीक्षा पूरी होने के संबंध में प्रमाणपत्र भी शामिल किया जाए ।
- (6) यदि किसी संस्था को पिछले चार बैंकों के दौरान किसी एक वर्ष में, जिसमें चालू वर्ष भी शामिल हैं, हानि कुई हो तो हानि होने के विस्तृत कारण दिए जाएं और साथ ही पुनः लाभकारिता प्राप्त करने के लिए उक्त सोसाइटी द्वारा उठाए गए विशिष्ट कदमों का भी उक्त टिप्पण में उल्लेख किया जाए ।
- (7) सोसाइटी की उपविधियों की एक प्रति ।
- (8) सोसाइटी की अधिकतम ऋण लेने की सीमा का प्रमाण पत्र ।

(9) परिशिष्ट-III के अनुसार एक विवरण भेजा जा जिसमें अंतिम सहकारी बैंक के अन्न में स्वामित्वाधीन निधि के प्रयोग्य भाग का उल्लेख किया जाए।

2. नियातीव्र में गारंटी अधेक्षित है उसमें कम से कम तीन माह पूर्व उपर्युक्त आधार पर प्रस्ताव चार प्रतियों में नैयार किया जाए और एक प्रति वित्तदायी बैंक को नकद सावधान की मंजूरी के लिए प्रस्तुत की जाए। दूसरी प्रति सहकारी समितियों के राज्य पंजीयक को, भारत सरकार को अपनी सिफारिशें भेजने के लिए प्रस्तुत की जाए और एक अन्य प्रति भारत सरकार को अग्रिम प्रति के रूप में भेजी जाए।

3. एक प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से गारंटी शुल्क भुगतान और लेखा अविकारी नागरिक पूति विभाग के नाम से बनवाए गए दिनों में देव डिसाइड इंस्टट के जरिए आवेदन के साथ भेजा जाए।

4. आवेदन प्राप्त होने पर, प्रस्ताव पर विचार करने के बाद बैंक के मामले को परिशिष्ट-IV में दिए गए प्रपत्र में भारत सरकार को सिफारिश के साथ भेजेगा। मामले की सिफारिश करते समय इस योजना के पैरा 10 की ओर बैंक का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया जाना है।

5. दूसरी अग्रिम प्रति प्राप्त होने पर सहकारी समितियों के पंजीयक परिशिष्ट-V पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार सूचना देते हुए अपनी सिफारिश के साथ मामला भारत सरकार को भेजेंगे। इस संबंध में उनमें ध्यान इस योजना के पैरा 14 की ओर आकर्षित किया जाता है।

6. वित्तदायी बैंक और सहकारी समितियों के पंजीयक की सिफारिशें उम तारीख से कम से कम एक माह पूर्व इस मंत्रालय को भेज दी जानी चाहिए, जिस तारीख में केन्द्रीय सरकार की गारंटी अधेक्षित है।

7. अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं भिया जाएगा।

परिशिष्ट-1

केन्द्रीय सरकार प्रथाभूति योजना के अन्तर्गत वित्तदायी बैंक से कार्यकारी पूँजी ऋण के लिए आवेदन करने वाले सहकारी संस्था द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले व्यौरे (नवीनतम आंकड़ों पर आधारित)

1. सोसाइटी का नाम और पूरा पता :

2. गृह करने की तारीख सहित पंजीकरण की तारीख :

3. (क)

सदस्यों की संख्या

अंश पूँजी की राशि
(लाख रु. में)

(1) व्यक्ति

(2) सोसाइटी/संस्थान

(3) सरकार

(4) कुल :

(ख) निदेशक मंडल का स्वरूप :

(1) निर्वाचित सदस्य

(2) नामित सदस्य

(3) कुल :

4. उधार लेने की शक्तियाँ ~

(क) बैंक से ऋण लेने की शक्तियों और सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा स्वीकृत कुल ऋण सीमा के बारे में सोसायटी के उप-नियमों/नियमों की संदर्भ का उल्लेख करें।

(ख) सोसायटी के प्रबंधकों द्वारा एक नियमित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए जिसमें सोसायटी की ऋण लेने की सीमा का उल्लेख किया गया हो।

5. केन्द्रीय सरकार प्रत्याभूति योजना के अन्तर्गत बैंक से ऋण और अधिक प्राप्त करने और इस संबंध में सोसायटी की तरफ से कागजात पर हस्ताक्षर भी करने के बासे सोसायटी के पदाधिकारी को प्राधिकृत करने हेतु एक संकल्प (प्रपत्र परिशिष्ट-II में) निदेशक मंडल/प्रबंध समिति द्वारा पारित किया जाए और उसकी प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न की जाए। (व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करें।)

6. नकद ऋण सीमा का अधिकत्य जिसके लिए आवेदन किया गया है, उसके साथ निम्नलिखित के संबंध में सूचना भी दी जाए :

क्र.सं. सोसायटी द्वारा व्यापार की गई वस्तुएं/वस्तु-मूल

अनुमानित
वार्षिक बिक्री
(लाख रु. में)

रहतिया बारंबारित
(वार्षिक बिक्री ÷ १)
(आरंभिक स्टाक +
अंतिम स्टाक)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

7. वांछित ऋण मुद्रिधा का व्यौरा :

(क) नकद ऋण सीमा का आधार :

- (1) माल की गिरवी :
- (2) माल की बंधक :

(ख) अवधि जिसके लिए अधिक प्राप्ति की मांग की गई है। मांगे गए अधिक प्राप्ति की अवधि ।

8. कुल स्वामित्वाधीन निधि और स्वामित्वाधीन निधि का विनियोग्य अंश

(परिशिष्ट-III पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार)

9. गाड़ाओं की सं. ग्रामीण क्षेत्रों में

गंदी बस्ती और कमजोर वर्गों वाले क्षेत्रों में

समाज के अन्य वर्गों में

- (1) बहुविभागी भंडार
- (2) केवल उचित वर दुकानें
- (3) अन्य
- (4) कुल

10. विगत तीन महकारी वर्षों के दौरान बिक्री :

(लाख रु. में)

वर्ष

नियंत्रित वस्तुएं

गैर-नियंत्रित वस्तुएं

ग्रावश्यक मद्दें

कुल

(1)

(2)

(3)

11. पिछले सहकारी वर्ष के अंत में ऋणों का विवरण :

अधिकरण	प्रयोजन	मंजूर की गई	वर्ष के दौरान निकाला	वर्ष के अंत में बकाया ऋण
		कुल राशि	गया अधिकतम ऋण	
(1) सरकार				
	(क) विशिष्ट परियोजना हेतु			
	(ख) कार्यकारी पंजी हेतु			
(2) वित्तदायी बैंकों से				
(3) अन्य स्रोतों से				
	(कृपया उल्लेख करें)			
(4) कुल				

12. अंतिम दो लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और अंतिम सहकारिता वर्ष समाप्त होने तक बाब के वर्षों के प्रोफार्मा तुलन-पत्र लेखा परीक्षित लेखाओं, व्यापार, लाभ और हानि लेखाओं और तुलनपत्रों की एक प्रति संलग्न की जानी है। उस प्राधिकारी का उल्लेख करें जिसने लेखाओं की लेखा परीक्षा की है।

13. पंजीयक द्वारा प्रदत्त लेखा परीक्षा का वर्ण

14. यदि भंडार इस समय घाटे में चल रहा है तो उसके क्या कारण हैं तथा सोसायटी के संचालन और आर्थिक आत्मनिर्भरता में सुधार लाने के लिए कार्य योजना सहित उद्ग्राए गए उपचारात्मक कदमों का व्यूहा वें एक अलग टिप्पण में उल्लेख करने हुए इस प्रोफार्मा के साथ संलग्न करें।

15. मंस्थान द्वारा प्राप्त अब तक उपयोग की गई गारंटी सुविधा/पुनर्वास सहायता का व्यूहा:

16. वित्तदायी बैंक की ऋणों/किसी भुगतान न कर पाने के कारण, यदि कोई हो :

17. 1 प्रतिशत प्रत्याभूति शुल्क चुकाने वाले डिमाण्ड फ्रूट का व्यूहा :

सोसायटी के अध्यक्ष/
महाप्रबंधक/सचिव के हस्ताक्षर

परिशिष्ट-II

निवेशक मंडल की को हुई बैठक की कार्यवाही से उद्धरण।

कार्यसूची

केन्द्रीय सरकार गारंटी योजना के तहत बैंक से रु. क नकद ऋण/रेहन ऋण प्राप्त करने तथा साथ ही इस बारे में समिति की ओर से व्यक्ति/व्यक्तियों को कागजात पर हस्ताक्षर करने के निए प्राधिकृत करने के प्रस्ताव पर विचार करना।

कार्यवाही

संकल्प किया जाता है कि बैंक से वस्तुओं के बंधक/रहन के प्रति में तक की अवधि के लिए, केन्द्रीय सरकार गारंटी योजना के तहत रु. की एक नकद ऋण संभाल के लिए आवेदन किया जाए। यह भी संकल्प किया जाता है कि श्री और श्री को ऋण व केन्द्रीय सरकार की गारंटी की मंजूरी प्राप्त करने के लिए समिति की ओर से करार करने तथा सभी आवश्यक विलेख व वंध-पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया जाए।

समिति का नाम

(नांख रु. में)

1. स्वामित्वाधीन निधि

- (1) अंश-पूँजी
- (2) सावधिक आरक्षित निधि
- (3) अन्य आरक्षित निधि
- (4) योग (क)

2. निवेश

- (क) (1) अन्य संस्थाओं में अंश
- (2) आवधिक अथवा अन्य जमा (आरक्षित निधि, जमा को छोड़कर)
- (3) स्थार्यः परिसम्पत्तियाँ
- (4) व्यापार के बाहर निवेश को गई आरक्षित निधि

योग :

(ख) स्थार्यः परिसम्पत्तियों हेतु प्राप्त अद्दण और राज-महायता
घटाएँ :

(ग) स्वामित्वाधीन निधि में से निवेश (क—ख) (ख)

स्वामित्वाधीन निधि का निवल प्रयोज्य अंश (क—ख) पिछले वर्ष के लिए
नियत विक्री का लक्ष्य वर्ष के दौरान की गई विक्री अगले वर्ष के
लिए प्रस्तावित विक्री लक्ष्य

परिशिष्ट-IV

बैंक की संस्तुति का प्रारूप

सेवा में,

निदेशक (सी.एफ.एस.)
खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय,
नागरिक पूर्ति विभाग,
कृषि भवन, नई विली।

विषय :—केन्द्रीय सरकार गारंटी योजना के अन्तर्गत
संघ/सोसाइटी/भंडार कोरु. के लिए नकद अद्दण संभा की मंजूरी के
मंबंध में ।

महोदय,

हम केन्द्रीय सरकार गारंटी योजना के अन्तर्गत सोसाइटी
से प्राप्तरु. की नकद अद्दण संभा की मंजूरी हेतु प्रस्ताव की एक प्रति
साथ में भेज रहे हैं। इस बैंक ने तक की अवधि के लिए

..... सामान्य मार्जिनों पर संस्था
 का नाम को रु. की; नकद शृणु/बंधक शृणु सीमा
 मंजूर की है। समिति के पक्ष में केंद्रीय सरकार की गारंटी हमें मिल जाने के बाद 10% मार्जिन पर बंधक और/अथवा रेहन रखी गई वस्तु पर समिति को नकद शृणु सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति दे दी जाएगी।

प्रमाणित किया जाता है कि समिति शृणु की किश्तों का नियमित रूप से भुगतान कर रही है तथा समिति के संचालन के विस्तृत कोई शिकायत नहीं है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार को समाप्त
 अवधि के लिए (संस्था का नाम) को रु. की नकद शृणु सीमा के बास्ते केन्द्रीय सरकार की गारंटी मंजूर करने की छपा करें।

भवर्दाय,
 प्रबंधक/अधिकारी

परिणाम-V

महकारी समितियों को केन्द्रीय सरकार की गारंटी का सिफारिश करने समय सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले द्वारा

1. सोसाइटी का नाम :

2. गत तीन वर्षों के कार्य के परिणाम :

(लाख रु. में)

वर्ष

बिक्री

निवल लाभ/निवल हानि

3. लेखा परिक्षा की स्थिति :

(क) अवधि जब तक संस्थान के लेखा की लेखा-परिक्षा की गई है :

(ख) यदि लेखा अद्यतन नहीं है, तो लंबित पड़े लेखाओं को पूरा करने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदम :

4. निरीक्षण :

(क) सरकार के अधिकारियों द्वारा सोसाइटी के निरीक्षण की तारीख ।

(ख) भंडार के कार्य में देखी गई खामियां

(ग) खामियों को दूर करने के लिए उठाए गए कदम :

5. नकद शृणु सीमा के लिए याशि और गारंटी की अवधि का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार की सिफारिश :

6. कृपया बताएं कि क्या तिमाही प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत की जा रही है :

महकारी समितियों के पंजीयक

नोट:—विणिष्ट सिफारिश के अन्तर्व में प्रस्ताव को माना नहीं जा सकेगा।

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

New Delhi, the 1st November, 1990

NOTIFICATION

(No. O-17011|2|89-CFS).—The Government of India notified in their notification No. O-17011|5|82-GOP dated 17th June, 1985, the continuance of the scheme of Central Government Guarantee as the fifth phase for a period from 1-4-85 to 31-3-90 to enable the Consumer Cooperatives and other cooperative institutions specified there in, to secure working capital loans from banking agencies on reduced margins during the 7th Plan period.

2. Having considered the increasing need for working capital requirements of the consumer co-operatives from banking institutions at reduced margin of 10%, it has been decided by the Government of India to operate the scheme of the Central Government Guarantee for a further period of 5 years from 1-4-1990 to 31-3-1995 (i. e., 8th Plan period).

3. All the Cooperative Societies availing of working capital loans from banking institutions under the scheme will have to pay a guarantee fee of 1% per annum.

4. In pursuance of the above decision the Government of India will consider entering into agreements in the form of Deed of Guarantee at Annexure-I, with any Apex|District Central Co-operative Bank, and bank constituted and functioning under banking companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970|State Bank of India, constituted under the State Bank of India Act 1955, a subsidiary Bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks Act, 1959) in respect of secured advances made by them to :—

- (i) National Cooperative Consumers' Federation.
- (ii) All State Federation of Consumer Co-operative.
- (iii) All Wholesale|Central Consumers Co-operative Societies.
- (iv) All State level Cooperative Federation engaged in the business of consumer articles registered under any nomenclature provided that their coverage under this guarantee scheme will be restricted to their working capital requirements for distribution of consumer articles alone.
- (v) All Cooperative institutions engaged in retail business in the distribution of consumer articles registered with whatsoever nomenclature and having sales turnover of at least Rs. 20 lakhs and in case of such institutions in the cooperatively underdeveloped states (Assam, Bihar, Meghalaya, Orissa, Rajasthan, West Bengal, Manipur, Tripura, and Nagaland) having

the minimum annual sales turnover of Rs. 10 lakhs.

5. The Central Government Guarantee will be available only in respect of secured loans and advances guaranteed for specific periods before 1-4-1995 with the prior approval in writing of the Surety, against pledge or hypothecation of goods, which would include book debts securities, investments and other moveable property, to all cooperative institutions mentioned in para 4(i) to 4(v) above. The banks have to keep a margin of 10 percent only on such loans and advances. The liability under the Central Government's Guarantee in respect of any such loans and advances to any society will be limited to :

- (i) 25% of the amount of all guaranteed loans and advances actually outstanding on the books of the bank against the cooperative society on the date on which the notice of demand is issued by the bank in accordance with the terms of the agreement.

OR

Rs. 150 lakhs (Rupees one crore & fifty lakhs) in the case of the National Cooperative Consumer' Federation, Rs. 100 lakhs (Rupees one crore) in the case of all State Level Federations including Co-operative institutions mentioned in para 4(iv) and Rs. 60 lakhs (Rupees sixty lakhs) in the case of all other cooperative institutions including those mentioned in para 4(v) irrespective of their place of business in metropolitan cities or elsewhere, whichever amount is less.

6. The guarantee in pursuance of this Notification will be available only in respect of secured loans and advances granted, for specific periods, with the prior approval in writing of the Central Government before the 1st April, 1995. No loan or advance granted for the first time on or after the 1st April, 1995 and no increase in the amount outstanding in respect of any loan or advance subsisting on the 31st March, 1995 shall be covered by the guarantee. The Central Government's liability on account of this guarantee shall become determined at the close of business on the 31st March, 1995.

7. The society shall enter into an agreement with the President of India in the form provided in the First Schedule to the Deed of Guarantee, annexed hereto, undertaking:—

- (a) To pay the dues of the bank regularly and promptly in accordance with the conditions laid down by the bank while sanctioning the loan, advance or cash credit;
- (b) To carry on the business of the society diligently with a view to making profit;

- (c) To guarantee to the Central Government repayment of all moneys that may be recovered by the bank from the Central Government on account of any default on the part of the society to make payment to the bank on demand without demur;
- (d) To implement a system of regular verification of stocks, followed by prompt assessment of shortages, fixation of responsibility therefore and recovery of their value from those responsible;
- (e) To exercise strict caution in the extension of credit facilities to societies, institutions, and individuals, combined with measures for systematic and prompt recovery;
- (f) To ensure preparation of quarterly trading and profit and loss accounts and balance sheet as on the last day of each quarter, together with preparation of a quarterly management report on the society's working and submit a copy of it to the Central Government and to the State Government every quarter;
- (g) To keep the properties and assets of the society free from encumbrances and attachments except those in favour of the Bank and in respect of which the Government has given guarantee to the Bank or those in favour of State|Central Government ; and
- (h) To provide all facilities to the Central Government or any person or persons nominated by it in this behalf to examine the accounts of the society and its working.

The agreement shall be executed before the date of drawal of the money. The Bank shall not make any payment unless the signed agreement and the Letter of Consent in the form provided in the second schedule to the Deed of Guarantee are furnished.

8. The Central Government's guarantee does not extend to the interest on the loans and advances granted by banks.

9. Every bank shall continue to hold all the promissory notes and unrealised securities which may be available to the bank in respect of such loans granted by it to the society even after realisation by it in full, of the outstanding dues to it in respect of the loans and advances advanced by it under the Central Government Guarantee, till the amount reimbursed by the Central Government as guarantor is realised.

10. The bank shall obtain from the society and furnish to the Central Government, a Letter of Consent by the society as in the Second Schedule to the Deed of Guarantee, to the effect that the society agrees to:—

- (a) Continue to pay interest on any amount paid to the bank by the Central Government in pursuance of the guarantee at the same rate at which interest has been or may be charged by the bank on the loan or advance made to the society until the said amount is paid

to or adjusted in favour of the Central Government ;

- (b) Credit or permit the bank to credit to the account of the surety all the amounts paid by or recovered from the society on account of the loan or advance, after the date on which the Central Government have reimbursed any amount to the bank in pursuance of the guarantee but after the bank's claim in respect of the loans and advances covered by the guarantee has been fully satisfied and so long as the amount paid by or recovered from the society on account of the loan interest and charges thereon have not been reimbursed by the society ;
- (c) The bank continuing to have and to exercise all the rights over the securities in favour of the bank in respect of all such loans and advances till all such claims of the Central Government are satisfied; and
- (d) The bank transferring its rights and claims under such securities to the Central Government if so required by the latter.

11. In the event of the bank being satisfied that the society has failed to make regular remittances to the bank against the advance made under the guarantee or fails to obtain the prior approval of the surety in writing for the continuance of a guarantee before its expiry, the bank will not allow further drawals by the society at reduced margin and will continue to credit all further remittances, by the society to the account of the guarantee loan till it is fully repaid.

12. The Central Government's guarantee shall not be invoked on more than one occasion by the bank in respect of a particular society. The guarantee may be invoked at any time before the 1st April, 1955. The bank shall first issue a notice of demand on the society to pay the amount to it on account of the loans and advances granted to it by the bank and guaranteed by the Surety, within thirty days of the date on which the notice asking for such repayment is served by the bank. A copy of such notice should be endorsed to the surety simultaneously. On the expiry of the period of 30 days if the society does not make payment of the amounts, the bank may issue a notice of demand on the Central Government. The Central Government shall reimburse to the bank the amount payable to it under the guarantee within a period of 90 days, from the date of receipt of the bank's notice invoking the guarantee and claiming payment.

13. The bank seeking a guarantee in pursuance of this notification shall, in the event of the Government's guarantee being invoked in the case of any loan or advance, undertake to credit to the Central Government any sums which may be realised from the society after the bank has realised from the society in full the loans and advances guaranteed by the Central Government. It shall be obligatory on the bank to take action in the above manner after the Central Government has reimbursed the amount under the guarantee.

14. The obligations of the bank referred to in the above clauses shall continue till such time as the amount reimbursed by the Central Government under the guarantee has been paid or credited to the Central Government or until the Central Government has agreed to adjust the said amount against any other amount due to be paid by it to the bank or to the society or to waive recovery of the amount.

15. The Registrar of Cooperative Societies of the concerned State/UTs is legally and administratively the competent authority for exercising regular supervision over the working of the society and also for taking appropriate remedial measures incase any adverse features are noticed in the affairs and working of the society, or if there is any report by the bank irregard to irregular remittances by the society or any other undesirable financial features in its operation. It is clearly understood that this guarantee will be given only if the proposal is recommended by the Registrar of Cooperative Societies of the concerned State/UTs. A recommendation made by the Registrar of Cooperative Societies will be deemed to be an assurance by such Registrar that necessary steps will be the authority to enter into the prescribed agreement of the society and that appropriate remedial measures will be taken in case of any such adverse report received from the tank or from the Government of India on the affairs and working of the society.

16. Any officer of the rank of Director/Deputy Secretary and above in the Ministry of Government of India dealing in Consumer Cooperatives, New Delhi duly nominated by the competent authority will be the authority to enter into the prescribed agreement of guarantee with the banks for the Central Government Guarantee in pursuance of this notification. All banks referred to in the notification are advised to contract the officer incharge of the Guarantee and operation in the Ministry as indicated above in case they wish to avail themselves of the facility provided by the Central Government.

Dr. P. K. MONGA, Director

ANNEXURE

DEED OF GUARANTEE

This deed of Guarantee entered into on the _____ day of _____ between the President of India (Hereinafter called "the Surety") of the one part and the _____ a bank constituted and functioning under the Banking Companies (Acquisition and transfer of Undertakings) Act, 1970|State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955| _____ (Name of the Bank), a subsidiary Bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959|a Cooperative Society registered under _____ and having its _____ office at _____ of the other part witnesseth as follows :

In consideration of the Bank making loans and advances to _____ (hereinafter

called the Society) at the latter's request, after relaxing margins which the Bank but for this guarantee might have normally kept, the Surety hereby guarantee to the Bank to the extent hereinafter provided the repayment of loans and advances by the society to the Bank subject to their terms and conditions hereinafter mentioned :—

1. The Surety's guarantee will be available only in respect of any secured loan or advance granted for specific periods to the society with the prior approval in writing of the Surety by the Bank before the 1st April, 1995 against the pledge or hypothecation of goods, which would include book debts, securities investments and other movable property. The Bank agrees to keep a margin of only 10% against such loans and advances.

2. The Surety's liability in respect of any loan or advance granted as above to the said society shall not at any time exceed :—

(i) twenty-five per cent of the amount of the guaranteed loans and advances actually outstanding on the books of the Bank against the society on the date on which the notice of demand on the Surety is issued by the Bank in accordance with the provisions of the clause (3) hereof :—

OR

(ii) Rs. _____ lakhs only, whichever amount is less.

3. The Bank may invoke the Surety's guarantee at any time before the 1st of April, 1995 in the manner hereinafter specified, namely :—

(i) The Bank shall first issue a notice of demand on the society to pay the amount due to it on account of the loans and advances granted to it by the Bank and guaranteed by the Surety, within thirty days of the date on which the notice asking for such repayment is served by the Bank. A copy of such notice should be endorsed to the Surety simultaneously.

(ii) If on the expiry of the period of 30 days, as aforesaid, the society does not make payment of the loans and advances granted to it by the Bank and guaranteed by the Surety, the Bank shall issue a notice of demand on the Surety.

(iii) The Bank shall while invoking Surety's guarantee, furnish to the Surety :—

(i) details of the goods, against which loan or advance in respect of which the guarantee is invoked has been granted.

(ii) the market value of the said goods, and

(iii) the amounts outstanding against the society as a :—

(a) the date on which the notice asking for repayment was issued to the Society by the Bank; and

(b) the expiry of thirty days of the date of notice asking for repayment, and

(iv) The Surety shall reimburse to the bank the amount due to it to the extent provided in this guarantee within a period of 90 days from the date of receipt by the Surety of the Bank's notice invoking the guarantee and claiming payment.

4. The guarantee herein contained shall be enforceable against, the Surety notwithstanding that any securities that the Bank may obtain from the Society shall be outstanding or unrealised.

5. The society shall enter into an agreement with the President of India in the form annexed in the First Schedule to the deed of Guarantee, undertaking :—

- (a) to pay the dues of the Bank regularly and promptly in accordance with the conditions laid down by the Bank while sanctioning the loan, advance to cash credit;
- (b) to carry on the business of the society diligently with a view to making profit;
- (c) guaranteeing to the Central Government repayment of all monies that may be recovered by the Bank from the Central Government on account of any default on the part of the society to make payment othe Bank, on demand without demur;
- (d) to implement a system of regular verification of stocks, followed by prompt assessment of shortages, fixation of responsibility therefor and recovery of their value from those responsible;
- (e) to exercise strict caution in the extension of credit facilities o societies, institutions and individuals, combined with measures for systematic and prompt recovery ;
- (f) to ensure preparation of quarterly trading profit & loss accounts and balance sheet as on the last day of each quarter, together with preparation of a quarterly management report on the Society's working and submit a copy of it to the Surety every quarter;
- (g) to keep the properties and assets of the society free from encumbrances and attachments except those in favour of the Bank and in respect of which the Government has given guarantee to the Bank or those in favour of State|Central Governments; and
- (h) to provide all facilities to the Surety on any person or persons nominated by it in this behalf to examine its accounts and its working;

The Bank shall not make any payment to the Society unless the agreement in the proforma in the First Schedule and the letter of Consent as in the Second Schedule to the Deed of Guarantee are furnished to it duly executed by the parties.

6. The bank shall agree, in consideration of the guarantee which is available to it from the Surety:—

- (a) to pay or credit to the account of the Surety any amount which will be realised from the society after the date on which the Surety has reimbursed the amount guaranteed, after it has realised in full the loans and advances guaranteed by the Surety;
- (b) to retain all the promissory notes or unrealised securities which may be available to the Bank in respect of the loan granted by it to the society even after realisation by it in full of the outstandings due to it, till the amount reimbursed by the Surety is realised;
- (c) to obtain from the Society and to furnish to the Surety, a letter of consent in the form provided in the Second Schedule hereto ;
- (d) if so required by the Surety, to transfer all such promissory notes or securities to the Surety, and/or his nominee, after the Bank has realised in full the outstanding due to it, but if the Surety has not been reimbursed the amount paid by it, and
- (e) to obtain from the Society and furnish to the Surety an agreement in the form provided in the First Schedule to the Deed of guarantee annexed hereto, as provided in the Clause 1 hereto.

7. The Surety's guarantee will not extend to the interest on the loans and advances sanctioned to the Society.

8. The obligation of the Bank in pursuance of the provisions of clause (6) shall continue until such time as the amount reimbursed by the Surety has been paid or credited to the Surety, or until the Surety has agreed to adjust the said amount against any other amount due to be paid by it to the Bank or to the Society or to waive the recovery of the amount.

9. The Surety's guarantee shall not be invoked on more than one occasion by the Bank in respect of the society and if or after the Surety's guarantee has been invoked, any loan or advance is granted to the society on whose behalf any amount has been paid to the Bank by the Surety, any such loan or advance shall be at the Bank's own risk and the Surety will have no liability on account of such further loan or advance.

10. No loan or advance granted for the first time on or after the 1st April, 1995 and no increase in the amount outstanding in respect of any loan or advance subsisting on the 31st March, 1995 will be guaranteed by the Surety. The Surety's liability shall become determined at the close of business on the 31st March, 1995.

11. The Surety shall be entitled to obtain from the Bank such information and returns relating to the loans and advances in respect of which this guarantee is available to the Bank and the Bank shall furnish such information or return at such intervals and in such manner as may be specified or required by the Surety.

12. If there is any difference or dispute between the parties hereto, arising out of or in connection with this agreement or concerning the meaning or interpretation thereof or otherwise howsoever in relation to his agreement, the same shall be referred to the sole arbitration of the person holding for the time being the post of Additional Legal Adviser (Arbitration) to the Government of India and decision of the said officer shall be final and binding on both the parties. It will be no objection that the arbitrator is a Government servant, that he had to deal with the matters to which this guarantee relates or that, in course of his duties as a Government servant, he has expressed views on all or any of the matters in dispute or difference. The provisions of the Arbitration Act, 1940 or any statutory modification or re-enactment thereof shall apply to such arbitration. The arbitration proceedings shall be held at such place as the Arbitrator may decide. The Arbitrator shall be entitled with the consent of the parties, to extend from time to time, the time for making the award.

13. The Stamp duty, if any, payable on this Deed of Guarantee shall be borne by the President of India.

14. In witness whereof the Surety and the Bank have caused these presents to be duly executed the day and year above mentioned.

Signature of the Officer Incharge
(Guarantee and Operations)

In the Government of India, in the Ministry dealing in Consumer Coop. acting in the premises for and on behalf of the President of India.
In the presence of :—

Witnesses :

1. _____
2. _____

FIRST SCHEDULE

AGREEMENT

This agreement made this _____ day of _____ between _____ the President of India (hereinafter called "The Central Government" which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include his successors in Office and assigns) of the one part and _____ a cooperative society registered under the _____ and having its registered [central] head office at _____ (hereinafter referred to as "The Society" which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include its executors, administrators, representatives and permitted assigns and successors) on the other part, witnesseth as follows :—

In consideration of _____ Bank making loans, advances, cash credit limit and other banking facilities and accommodations to the Society, inter alia on the Central Govt. guaranteeing repayment of a part of the loan and advance made to the society by the Bank, the Society hereby undertakes to the Central Govt. :—

- (i) to pay the dues of the Bank regularly and promptly in accordance with the conditions laid down by the Bank while sanctioning the loan advance or cash credit;
- (ii) to carry on the business of the society diligently with a view to making profit;
- (iii) to implement a system of regular verification of stocks, followed by prompt assessment of shortages, fixation of responsibility therefor and recovery of their value from those responsible;
- (iv) to exercise strict caution in the extension of credit facilities to societies, institutions and individuals, combined with measures for systematic and prompt recovery;
- (v) to ensure preparation of quarterly trading and profit and loss accounts and balance sheet as on the last day of each quarter, together with preparation of a quarterly management report on the society's working and submit a copy of it to the Central Government and also to the State Government every quarter;
- (vi) to keep the properties and assets of the society free from encumbrances and attachments except those in favour of the Bank and in respect of which the Government has given guarantee to the Bank or those in favour of State/Central Govt.; and
- (vii) to provide all facilities to the Central Govt. or any person or persons nominated by it in this behalf to examine the accounts and its working.

2. The Society guarantees to the Central Govt. repayment of all monies that may be recovered by the Bank from the Central Govt. on account of any default on the part of the Society on demand without demur.

3. All disputes and differences arising out of or in any way touching or concerning this agreement, excepting Clause 2 above shall be referred to the Sole Arbitration of the person holding the post of Additional Legal Adviser (Arbitration) Govt. of India. It will be no objection that the arbitrator is a Govt. servant or that he had expressed views in all or any of the matters in dispute or difference. The provisions contained in the Indian Arbitration Act shall apply to such arbitrations. The award of the Arbitrator shall be final and binding on both the parties.

Signed by (name & designation)
for and on behalf of the
President of India.

Witnesses :

1. _____
2. _____

Signed by the Authorised representative(s) of the Society
(name and designation)

**SECOND SCHEDULE
LETTER OF CONSENT**

To

1. _____ Bank

2. President of India

In consideration of the President of India (hereinafter referred to as the President) having agreed to guarantee the repayment of a part of the loans and advances made to the (Name of the Society) _____ by the (Name of Bank) _____

(hereinafter referred to be "the Bank"), we hereby agree that any promissory note and any security by way of pledge, or hypothecation of goods, which would include book debts, securities, inventories and other moveable property, that we have given and may give to Bank in connection with such loans and advances shall be subsisting and may be retained by the bank, notwithstanding the fact that in pursuance of the guarantee given to the Bank by the President, the President may have made good any deficit in our account.

We further agree:—

- (a) to continue to pay interest on any amount paid to the Bank by the President in pursuance of the President's guarantee at the same rate at which interest has been or may be charged by the Bank on the loan or advance made to us till the said amount is paid to or adjusted in favour of the President;
- (b) to credit or to permit the Bank to credit to the account of the Surety of all the amounts paid by or recovered from us on account of the loan or advance, after the date on which the President has reimbursed any amount to the Bank in pursuance of the President's guarantee but after the Bank's claim in respect of the loans and advances covered by the President's guarantee has been fully satisfied and so long as the amounts reimbursed by the President together with the interest and charges thereon have not been reimbursed by us;
- (c) to the Bank continuing to have and to exercise all the rights over the securities in favour of the Bank in respect of all such loans and advances till all such claims of the President as are referred to in clause (b) are also satisfied; and
- (d) to the Bank transferring its rights and claims under such securities to the President, if so required by or on his behalf.

Witnesses :

1. _____

2. _____

Signature by the Authorised
representative(s) of the
Society (Name & Designation)

ANNEXURE-II

Procedure for submission of proposed for sanction of Central Government Guarantee for obtaining working capital loan at reduced margin from the Nationalised Cooperative Banks under the Central Government Guarantee Scheme circulated vide notification No. O-17011/2/89-CFS dated 1-11-90

The institution seeking Central Government Guarantee shall have to submit proposed with the following information and documents :—

- (i) Particulars of the institution in the prescribed form (Appendix-I) alongwith the reasons if there is any shortfall in its sales and profitability during any particular year.
- (ii) Resolution of the Board of Directors (Appendix-II) not earlier than three months from the date of application indicating the decision of the institution to obtain the working capital loan from a particular bank under Central Government Guarantee and also authorising the persons to sign necessary declared documents.
- (iii) Agreement form as given at first schedule of the notification duly signed by the authorised persons and two witnesses with full address.
- (iv) Letter of consent as given at a second schedule of the notification duly signed by the authorised persons alongwith two witnesses with full address.
- (v) Audited/proforma statement of accounts viz. Trading and Profit & Loss accounts and balance sheet—for last 4 cooperative years of which atleast audited statements of Accounts should be for two years alongwith proforma account for the subsequent half year/quarter. The certificate as regards completion of audit need to be incorporated.
- (vi) In case the institution which has incurred loss during any one of the four preceding years including the current one, detailed reasons for the loss as well as the specific steps initiated by the society to regain profitability may be indicated in above note.
- (vii) A copy of the by laws of the society.
- (viii) A certificate of maximum borrowing limit of the society.
- (ix) A statement indicating the disposable part of owned funds at the end of latest cooperative year as per Appendix-III.

2. Proposal on the above line is to be prepared in quadruplicate atleast three months in advance before the date from which the guarantee is required and one copy to be submitted to the financing bank for sanction of the cash credit loan, another copy to be submitted to the State Registrar of Cooperative

Societies for sending his recommendations to the Government of India and another copy to be sent to the Government of India as an advance copy.

The guarantee fee of 1% per annum will have to be sent through a Demand Draft drawn in favour of the PAO, Department of Civil Supplies payable at New Delhi alongwith the application.

4. On receipt of the application, after considering the proposal, the bank shall recommend the case to the Government of India in the proforma given at Appendix-IV, while recommending the case the bank's attention is particularly drawn to para 10 of the scheme.

5. On receipt of another advance copy the Registrar Coop. Societies will recommend the case to the Government of India alongwith the information as per proforma at Appendix-V. In this connection his attention is drawn to para 14 of the scheme.

6. The recommendations of the financing bank as well as the Registrar Cooperative Societies should be sent to this Ministry atleast one month in advance of the date from which the Central Government Guarantee is required.

7. Incomplete application will not be entertained

Appendix—J

Particulars to be furnished by the Cooperative Institution applying for working capital loan from financing bank under Central Government Guarantee Scheme. (To be based on the latest figure)

1. Name and full address of the Society.
2. Date of registration, alongwith date of commencement of operations.

3. (a)	Number of members	Amount of Share Capital
		(Rs. in lakhs)

- (i) Individuals
- (ii) Societies/Institutions
- (iii) Government
- (iv) Total

- (b) Composition of Board of Directors.
 - (i) Elected Members
 - (ii) Nominated Members
 - (iii) Total:

4. Borrowing powers:

- (a) Quote the number of Byelaws/Rules of the Society regarding powers to borrow from the bank and the overall borrowing limits approved by the Registrar of Cooperative Societies.
 - (b) A certificate in writing from the management of the Society should be furnished indicating the borrowing limit of the society.
5. A resolution authorising the office bearers of the society to obtain loans and advances from the bank under Central Government Guarantee scheme and also to sign the documents on behalf of the society in this respect should be passed by the Board of

(A proforma at appendix-II)

Directors/Committee of Management and a certified copy thereof should be attached with the application. (indicate the names of the persons)

6. Justification for cash credit limit applied for, which should inter-alia, contain information on following aspect:

Sl. No.	Commodities/group of commodities handled by the society	Anticipated Annual Sales (Rs. in lakhs)	Stock turn (Annual Sales — (Opening Stock plus Closing Stock)
---------	---	---	---

7. Particulars of credit facilities required :

- (a) Cash credit limit against:
 - (i) Pledge of goods.
 - (ii) Hypothecation of goods.
- (b) The period for which the advance is required.

8. Total owned funds and disposable part of owned funds. (as per proforma at appendix-III)

9. No. of branches
- | | | |
|----------------|---|---------------------------|
| In Rural areas | In slum areas and areas populated by weaker sections. | In other areas of society |
|----------------|---|---------------------------|
- (i) Deptt. Stores
 - (ii) Exclusive Fair price Shop
 - (iii) Others.
 - (iv) Total

10. Sales during last three Coop. Years.

(Rs. in lakhs)

Year	Controlled Commodities	Non-Controlled Commodities	Essential Items	Total
(i)				
(ii)				
(iii)				

11. Details of borrowings at the end of last Coop. Year.

Agency	Purpose	Total Amount sanctioned	Maximum borrowing during the year	Outstanding at the end of the year
--------	---------	-------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

- (i) Government
 - (a) For Specific Project
 - (b) For working capital

- (ii) From financing Banks
 - (iii) From other sources
(Please specify)
 - (iv) Total
12. Last two audited balance sheets and proforma balance sheets for subsequent years till the end of the last cooperative year (A copy of the audited accounts, trading, profit and loss accounts and balance sheets to be attached). Indicate the authority who had audited the accounts.
13. Audit classification awarded by the Registrar.
14. If the store is currently running in loss, reasons therefor and details of the remedial measures adopted, along with the programme of action for improving the functioning and economic viability of the society (To be furnished in a separate note to be attached to this proforma).
15. Details of Guarantee facilities availed/Rehabilitation assistance received by the Institution till today.
16. Reasons for failure to repay loans/installments to financing bank, if any.
17. Details of Demand Draft paying 1% Guarantee Fee.

Signature of the President/
General Manager/Secretary of
the Society.

Appendix-II

Extract from the proceedings of the meeting of the Board of Directors held on _____

Agenda	Proceedings
<p>To consider the Proposal for obtaining a cash credit/hypothecation loan of Rs. _____ from _____ Bank under the Central Government Guarantee Scheme and also to authorise the person/persons to sign the documents on behalf of the society in this regard.</p>	<p>It is resolved to apply to _____ bank for a cash credit limit against pledge/hypothecation of goods for Rs. _____ for the period from _____ to _____ under Central Government Guarantee Scheme. It is further resolved that Shri _____ and Shri _____ are authorised to enter into agreement and to sign and execute all necessary deed and bonds in this connection on behalf of the society for obtaining loan and sanction of Central Government Guarantee.</p>

Name of the Society

(Rs. in lakhs)

1. Owned funds
 - (i) Share capital
 - (ii) Statutory Reserves
 - (iii) Other reserve funds
 - (iv) Total (A)

2. Investment
 - (a) (i) Shares in other Institutions
 - (ii) Fixed or other deposits
(excluding reserve funds deposits).
 - (iii) Fixed Assets
 - (iv) Reserve funds invested outside the business.

Total:

(b) Less loans and subsidies received for fixed Assets.

(c) Investment from owned funds (a—b) (B)

Net disposable part of owned funds (A—B)

Sales target fixed for the preceding year

Sales achieved during the year

Sales target proposed for the next year

SAMPLE RECOMMENDATION OF THE BANK

To

wfi[

The Director (CFS)
Ministry of Food & Civil Supplies
Department of Civil Supplies
Krishi Bhawan
New Delhi

Subject: Sanction of cash credit limit for Rs. _____ under the Central Government Guarantee Scheme to _____ Federation/Society /Store—Regarding

Sir,

We are forwarding here with a copy of the proposal for sanction of cash credit limit of Rs. _____ under Central Government Guarantee Scheme received from _____ Society. The Bank has sanctioned a cash credit/hypothecation limit of Rs. _____ to the (Name

of the Institution) for period upto on normal margins. The society will be allowed to avail the cash credit facilities against pledge and/or hypothecation of goods at 10% margin after the receipts of the Central Government Guarantee to us in favour of the Society.

It is certified that the Society is repaying the loan instalments regularly and there is no complaint against the working of the society.

It is, therefore, requested that Government of India may please sanction Central Government Guarantee for a cash Credit limit of Rs. —————— to (Name of the Institution) —————— for the period ending. ——————

Yours faithfully,

Manager/Agnt

Appendix—V

Particulars to be furnished by the Registrar of Cooperative Societies while recommending Central Government Guarantee in favour of Consumer Cooperatives.

(Rs. in lakhs)

1. Name of the Society
2. Working Results for the last three years.

	Year	Sales	Net Prot/Net loss
--	------	-------	-------------------

3. Position of Audit:

- (a) The period upto which the accounts of the institution have been audited.
- (b) If audit is not upto date, steps taken/ proposed to be taken for ensuring completion of pending audit.

4. Inspection

- (a) Date of which the Society was last inspected by officers of the Government.
- (b) Shortcomings, if any noticed in the working of the Store.
- (c) Steps taken to remedy the shortcomings.

5. Recommendation of the State Government specifying the extent of cash credit limit and the period for which guarantee may be given.

6. Indicate whether the quarterly progress Reports are being submitted regularly.

Registrar Cooperative Societies

N.B. In absence of specific recommendations the proposal may not be agreed to.